3

रोजगार सचिव की मिलीभगत से भ्रष्टाचार

5

सच्चे समर्पित नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय

7

कलम के सिपाही में इस बार गजलकार दुष्यंत कमार

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 14 प्रति सोमवार, 12 अगस्त 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता से जलकुंभी से ढक रही बड़ी झील सहित अन्य झीलों की सुंदरता

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भोपाल के बड़े तालाब और कलियासोत बांध सहित अन्य जलस्त्रोतों में जलकुंभी की सफाई नहीं हो सकी है। कलियासोत में नेहरू नगर के पीछे और बड़े तालाब में सीहोर नाके पर बड़े स्तर पर जलकुंभी का फैलाव हो गया है। सफाई नहीं होने से ये दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि यदि समय पर जलकुंभी की सफाई

नहीं की गई तो इससे तालाब की जलीय जैव विविधता को खतरा हो सकता है। मछलियों और पानी के अंदर रहने वाले जीवों की मौत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलकुंभी के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। लगातार बने रहने के कारण पानी के अंदर रहने वाले जीवों को खतरा हो जाता है। जलकुंभी के कारण पानी का वाष्पीकरण भी 3 से 8 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इसकी तेजी से वृद्धि से जलीय जीवों और वनस्पति को प्राणवायु न मिलने से उनका दम घुटने लगता है। जलकुंभी वाले पानी में मच्छरों भी तेजी से पनपते हैं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम भोपाल ने भोपाल के 13 तालाबों और 58 कुएं-बावडिय़ों को श्रमदान के जरिए साफ करने का निर्णय लिया इसके लिये 3.70 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।

(शेष पेज 6 पर)

नक्सल प्रभावित जिलों में कारगर साबित हो रही है नियद नेल्लानार योजना

मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली, 375 ने किया आत्मसमर्पण

-समता पाठक

छत्तीसगढ़ राज्य जहां 33 जिलों में से 10 जिले गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से हर सरकार चाहे वह कांग्रेस की हो या भाजपा की नक्सलवाद सबके सामने सिरसा के मुंह जैसी समस्या बनकर खड़ा रहा है। हर

सरकार में अपनी तरह से नक्सलवाद की समस्या से निपटने की कोशिशें की हैं। राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार भी नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रयासरत है। कई योजनाओं को लागू कर नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें कर रही है साथ ही उनकी समस्याओं को दूर कर रही है। इसी के महत छत्तीसगढ़ राज्य में करीब छः माह पहले लागू हुई नियद नेल्लानार योजना यानि कि आपका अच्छा गांव योजना पूरे देश में मिशाल बनने जा रही है। इस योजना के लागू होने के कुछ महिनों में ही इसके सफल परिणाम दिखने शुरू हो गये हैं। सन 2005 में महेन्द्र कर्मा और तत्कालीन सरकार ने सामूहिक रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सलवा जुडूम आंदोलन की शुरूआत की थी। सलवा जुडूम जिसका अर्थ होता है शांति मार्च। सलवा जुडूम एक मिलिशिया था। यानि कि रक्षक योद्धाओं का एक समूह जो कि नक्सलवाद के खिलाफ हथियारबंद कार्यवाही के लिए सतत अग्रसर था। सलवा जुडूम का उद्देश्य नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करना था। (शेष पेज 6 पर)

क्या रीजनल इन्वेस्टर समिट और राउंड टेबल से आ रहे निवेश के प्रस्ताव बदल पायेंगे प्रदेश की तस्वीर?

कहीं महज एक आयोजन बनकर न रह जाये मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदेश की कमान संभाले हुए लगभग छह माह से अधिक का समय हो गया है। इस छह माह के कार्यकाल का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि मुख्यमंत्री यादव लगातार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर

फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले छह माह में तीन बार रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर चुके हैं और दो बार देश के बड़े बिजनेसमेन के साथ राउंट टेबल पर चर्चा कर चुके हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार इस तरह के आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की प्रगति की नींव रखने का कार्य कर रही है वहीं दूसरी तरफ राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस तरह के आयोजनों का भविष्य में क्या परिणाम आता है यह तो देखने वाली बात होगी। 28 अगस्त को ग्वालियर, और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव का आयोजन प्रस्तावित है। (शेष पेज 6 पर)

कार्पोरेट कंपनियों भारत छोड़ो आव्हान को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा धरना प्रदर्शन

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। 09 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी कार्पोरेट कंपनियों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अखिल भारतीय किसान सभा नरसिंहपुर द्वारा भगतसिंह चोक सालीचौका में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए नुक्कड़ सभा की गई। मध्य प्रदेश किसान सभा के संयुक्त सचिव कामरेड जगदीश पटेल ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई थीं जिसके परीणाम स्वरूप देश भर के 500 से अधिक किसान संगठनों ने एकजुट होकर दिल्ली की बार्डर को घेरते हुए 13 महीने से अधिक आंदोलन चला जिसमें 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, आखिर सरकार के प्रधानमन्त्री मोदी जी को 19नवंबर 2022को माफी मांगते हुए बिल वापसी की बात कही एवं सरकार के द्वारा एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसर एमएसपी, किसानों के कर्जे माफी पर चर्चा कर समाधान करने आंदोलन के दौरान बनाए गए मुकदमों को वापिस लेने सहित अन्य मुद्दों पर लिखित आश्वासन दीया इसके उपरांत मोरचा ने आंदोलन स्थगित किया था। लेकीन वायदा खिलाफी मोदी सरकार आज तक

एक कदम आगे नही बढ़ी, किसानों के साथ धोखा किया है। बाबजूद किसानों की समस्या सुलझाने के सरकार कार्पोरेट कंपनियों को संरक्षण देने लगातार किसान मजदूर एवं मेंहतक्ष वर्ग के खिलाफ़ जनविरोधी बिल लाती जा रही है।

सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई है जिसमें अब कार्पोरेट जहां भी किसी भी मद की वेशकीमती जमीन चाहेगा सरकार उसे किसान मजदूर या गांव नदी पहाड़ बिना भूस्वामियों की सहमति से छीनकर उनके सुपुर्द कर देगी, जो सरकार के अनुसर मुआवजा है संबंधित ले ले न भी ले तो सरकार उसे खजाने में जमा करेगी लेकीन जमीन छोड़ना ही पड़ेगा। इसके पर्व अधिग्रहण के पूर्व उस क्षेत्र की 70प्रतिशत जनता द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही अधिग्रहित कर सकते थे, और भी कार्पोरेट के हित इस बिल में समाहित है।

नुक्कड़ सभा को तहसील महासचिव करन सिंह अहिरवार, उपाध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, सहसाचिव नरेन्द्र वर्मा, रामसिंग वर्मा ने सम्बोधित करते हुए मूंग खरीदी, मंडियों में चोरी से लेकर, नकली खाद बीज, बिजली नियमानुसार किसानों को 10 घण्टे पूरी न मिलने संबंधित स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए शासन के जिम्मेवार लोगों को चेताया कि जो शासन द्वारा निर्धारीत मानदंड हैं उनके अनुरूप लोगो को सुविधाएं उपलब्ध कराएं अन्यथा उनका भी विरोध करने बाध्य होना पड़ेगा। सभा में किसान सभा के एड एल एन वर्मा, तुलसीराम श्रीवास, उदुराज वर्मा, नन्हेलाल वर्मा, कमलेश पटेल, रामनरायण पटेल, भैरो प्रसाद विश्वकर्मा, दीपक वर्मा, विश्राम वर्मा सहित सैंकड़ों किसान मौजूद रहे। (जगत फीचर्स)

जिला पदाधिकारी ने छात्र-छात्राओं को 1-1 पौधा लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने को प्रोत्साहित किया

-अमित राय

जगत प्रवाह. कोलकाता। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत जिला पदाधिकारी बक्सर, अंशुल अग्रवाल के द्वारा राजपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हेठुआ तालाब पर सघन वृक्षारोपण किया गया। जिला पदाधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा राजपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हेठुआ तालाब पर लगभग 400 पौधारोपण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निर्देशित किया गया कि पौधे की सुरक्षा हेतु चारों तरफ कटीले तार से घेराबंदी करना सुनिश्चित करेंगे। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा छात्र-छात्राओं को 1-1 पौधा लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने को प्रोत्साहित किया गया। इस क्रम में छात्र-छात्राओं से पेड़-पौधे के महत्व के बारे में भी पूछा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में यदि किसी लाभुक जिनके पास अपना जमीन हो एवं वे पौधारोपण हेतु इच्छुक हो तो ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से कार्य अवधि में संपर्क कर सकते हैं। मनरेगा अंतर्गत पोखर के किनारे पेवर ब्लॉक, इनलेट आउटलेट, पोखर के परिसर में ही चापाकल के किनारे सोख्ता का भी निर्माण किया गया है। पंचायती राज विभाग से ओपेन जिम भी अधिष्ठापित किया गया है। भविष्य में जब ये पौधे बडे हो जायेंगे तक पोखर का सुन्दरता और भी बढ़ जायेगी। वृक्षों की प्रजाति में गुलमोहर, महोगनी, नीम, अशोक, जामुन, अमरूद, इत्यादि पौधे रोपित किये जा रहे है। ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा मनरेगा अंतर्गत आठ वनपोषक को भी चयनित कर कार्य आवंटित कर दिया गया है। जिनका कार्य पौधे को पानी देना निराई गुणई करना, पौधों की सुरक्षा करना एवं अतरजिविता सुनिश्चित करना होगा। ये वनपोषक 05 वर्षों तक पौधों की देखभाल करेंगे। जिनको मनरेगा अंतर्गत प्रतिमाह 08 दिवस की मजदूरी दी जायेगी। (जगत फीचर्स)

यातायात पुलिस द्वारा स्कूल वाहनों की चैकिंग

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक विदिशा दीपक कुमार शुक्ला द्वारा दिए गए आदेश के पालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा डॉ. प्रशांत चौबे और एसडीओपी सिरोंज उमेश कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में स्कूल वाहन बस, मैजिक वैन, ऑटो रिक्शा को चैक किया एवं चालानी कार्यवाही में आज 07 वाहनों

पर रु.13500/– जुर्माना किया गया, कुछ दिनों पहले स्कूल वाहन चालकों की बैठक ली थी और सभी को वाहन संबंधी कागजात पूर्ण रखने एवं क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाने का बताया गया था परंतु फिर भी जिन वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है उन सभी पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। (जगत फीचर्स)

मढई में पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने कलेक्टर ने किया भ्रमण

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना गुरुवार को मढई में पहुंचकर पर्यटकों को और अत्यधिक सुविधा मुहैया कराने की संभावनाओं को तलाशा। उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एल कृष्णमूर्ति के साथ पर्यटक संभावना वाले स्थान का भ्रमण किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के टिकट काउंटर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने की जगह देखी। बताया गया कि इंटर प्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जिससे भविष्य में पर्यटकों को काफी लाभ होगा। उन्होंने पर्यटन की जगह का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने के लिए सोहागपुर के एसडीएम बृजेंद्र रावत एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा की मढई में पर्यटकों को और आकर्षक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पर्यटकों को मढई आने के लिए प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एल कृष्णमूर्ति, जल संसाधन जल संसाधन विभाग के श्री राजपूत नायब तहसीलदार, अंजू लोधी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के असिस्टेंट डायरेक्टर अंकित जामोद, रेंजर बालासर कर उपस्थित रहे।

(जगत फीचर्स)

अवैध कालोनी काटने वाले मां बेटे की कमिश्नर से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर के राहतगांव रोड टिमरन नदी के किनारे मां बेटे द्वारा अवैध कॉलोनी काटे जाने और गुमराह कर फर्जी तरीके से प्लाट बेचे जाने के मामले में कमिश्नर से शिकायत करते हुए शीघ्र ही कॉलोनाइजर अमन यादव एवं उसकी मां शरदाबाई यादव पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। वहीं अवैध कॉलोनी की शिकायत को लेकर कई बार स्थानीय निवासियों एवं पत्रकार उत्तम गिरी द्वारा एसडीएम कलेक्टर को भी की गई थी। आए दिन समाचार पत्रों में भी खबरें लगातार प्रकाशित की गई जिसको लेकर एसडीएम महेश बडोले द्वारा अवैध कॉलोनी की रिपोर्ट एवं प्रकरण बनाकर कलेक्टर को फाइल भेज दी है। अब अवैध कॉलोनी नाइजर मां बेटे पर कड़ी कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय से होनी है। इसी को लेकर नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर गोपाल कृष्ण तिवारी से शिकायत कर शीघ्र ही कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है।

सीएम के आदेश का अधिकारी नही कर रहे पालन

मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगातार अवैध कॉलोनी को लेकर कड़ी कार्रवाई करने व कॉलोनी नाइजर पर सीधे एफआईआर दर्ज किए जाने का दावा कर रहे हैं तो वही जिले के कलेक्टर भी आए दिन अवैध कॉलोनीनाइजर पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। किंतु इस अवैध कॉलोनी के मामले को लेकर लगातार पिछले पांच महीने से शिकायत की जा रही है और आए दिन समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हो रही है इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा अब तक इन अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजर अमन यादव एवं शारदा बाई यादव के खिलाफ कोई भी कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई।

एसडीएम ने अवैध कॉलोनी का प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भेजा

नगर परिषद को लगाया लाखों का चूना

नगरीय सीमा में आने वाली कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले कॉलोनी नाइजर से अगर नगर परिषद कार्रवाई करते हुए विकास शुल्क टैक्स आदि की वसूली करती तो लगभग 20 लाख रुपए से अधिक की राजस्व आय नगर परिषद की बढ़ती किंतु नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण विकास शुल्क और टैक्स के नाम पर मिलने वाली लगभग 20 लाख रुपए की राशि का आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं कॉलोनाइजर टैक्स एवं विकास शुल्क की चोरी करते हुए मनमाने दामों पर प्लाट बेच रहे हैं और लगभग 35 से 40 प्लाट की रजिस्ट्री भी कर चुके हैं किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से कॉलोनी नजर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।*(जगत फीचर्स)*

इनका कहना है

रहटगांव रोड टिमरन नदी के किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी का प्रकरण रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को भेज दिया गया है अब आगे की करवाई वहीं से होगी।
महेश बडोले, एसडीएम टिमरनी

प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर की कार्यवाही की मांग

पुलिस ने बहशीपन दिखाते हुए बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाकर शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से चल रहे कांग्रेस के आंदोलन को कुचलने का अनुचित कृत्य किया: अरूण यादव

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। इन्दौर नगर निगम कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए लाठी चार्ज की जांच की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरूण यादव के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के डीजीपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव, पूर्व मंत्री संज्जन सिंह वर्मा, मप्र कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, पूर्वमंत्री पी.सी. शर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, विधायक आरिफ मसूद, प्रदेश कांग्रेस विभाग एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया, महामंत्री संजय कामले, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, प्रवक्ता रवि सक्सेना, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षद्वय प्रवीण सक्सेना और अनोखी मानसिंह पटेल आदि ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सौंपे गये ज्ञापन में कहा कि इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रूपयों के घोटाले और भारी भ्रष्टाचार के विरोध में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में विगत 6 अगस्त को इंदौर के नगर निगम मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। प्रदर्शन के बाद नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन देने जीतू पटवारी सहित अन्य नेतागण एवं कार्यकर्ता जाने लगे तभी पुलिस अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेताओं पर वाटर कैनन की बौछार की गई और बेरिकेट्स के पीछे छुपके बैठे पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के इशारे पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर उन्हें घायल कर दिया। जिसके वायरल वीडियो को मीडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चेनल्स पर भी दिखाया गया व समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुये।

कांग्रेस नेताओं ने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पुलिस ने किस तरह बहशीपन दिखाते हुए बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाकर शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से चल रहे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को कुचलने का अनुचित कृत्य किया है। जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेताओं के घायल होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी घायल हुए हैं। *(जगत फीचर्स)*

रोजगार सचिव की मिलीभगत से निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर देवरी जनपद पंचायत पहुंचे आला अधिकारी

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी कला। मामला ग्राम पंचायत पिपरिया पाठक के खेरी पदम का है, जहां पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से वंचित रखा गया है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन पर्ची, निर्माण कार्यों सहित सीसी रोड नाली, नाडेफ, सोकपिट, आदि में रोजगार सचिव राकेश पटेल उर्फ दिनेश वंश टिकरया द्वारा किए गए भ्रष्टचार को लेकर पिपरिया पाठक के ग्रामीणों द्वारा कई बार लिखित आवेदन सीईओ मनीषा चतुर्वेदी को दिए। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।

जिस कारण ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित होकर

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी और कार्यालय में जनसुनवाई के समय लिखित आवेदन दिया।तब एसडीएम द्वारा देवरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आला अधिकारियों की टीम गठित की है। देवेन्द्र प्रजापति ने बताया है कि रोजगार सचिव द्वारा पीएम आवास योजना के नंबर पैसे की मांग की जाती है ग्रामीणों ने कहा है कि रोजगार सचिव द्वारा जितना भी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है उसकी वसूली की जाए और जिस जिस से आवास के नाम पर दस दस हजार रुपये लिए हैं वह वापस दिए जाएं और जो पात्र व्यक्ति है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
(जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे प्रहार

बांग्लादेश में शुरू हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन अंततः इतना तीव्र हुआ कि देश में तख्तापलट हो गया। सेना ने सत्ता की कमान संभाल ली है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। देश में अराजकता का माहौल है। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। पड़ोसी देश के हालात दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी भी वहां पर हालात अस्थिर हैं। बांग्लादेश में पिछले महीने शुरू हुए प्रदर्शन और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर काफी प्रहार किये जा रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ ही हिंदुओं को निशाना बनाकर जानमाल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। धार्मिर स्थंलों और हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। जिसकी वजह से वहां हिंदु दहशत में हैं।

इन सारी घटनाओं को लेकर भारत चिंतित है। चिंतित होने की दो वजहें हैं- पहली यह कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और पिछले कुछ वर्षों से शेख हसीना सरकार से संबंध बेहतर रहे हैं। सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश की हमारे लिए अहमियत है। खासकर चीन को लेकर जो तनातनी चलती है उसमें बांग्लादेश बहुत उपयोगी देश साबित होता है। यही वजह है कि बांग्लादेश के मौजूदा बिगड़े हालातों से चीन खुश नजर आ रहा है। चीन इन हालातों से भारत को लेकर अपने हित साधते हुए देख रहा है। भारत की दूसरी चिंता वहां के हिंदुओं को लेकर है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। देश में 01 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं, उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 07 प्रतिशत हिंदू इन दिनों खौफ के साये में हैं। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को यहां निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार हालात और भी अलग हैं। पलायान को मजबूर हैं।

आपको बता दें कि बांग्लादेश में बिगड़े हालातों की बात की जाये तो वह कुछ इस प्रकार है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविस सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच झड़पें शुरू हो गईं, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।

बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए लगता है भारत की चिंता घुसपैठियों को लेकर होगी। क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर सीमा भारत से मिलती हैं। और हजारों की संख्या में लोग भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंच रहे हैं। भारत की समस्या है कि इन्हें कब शरण देने से रोका जा सकता है। जिनमें ज्यादातर हिंदु हैं और इन पर ही बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। यदि इनको शरण देते हैं तो देश के अंदर अराजकता तो फैलेगी ही साथ ही कई असामाजिक तत्व भी देश के अंदर घुस आयेंगे। ऐसी स्थिति में भारत को आने वाले समय में बहुत ही सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। यह भी ख्याल रखना होगा कि भारत के कदम से यहां की शांति और सौहार्द्ध भी न बिगड़ पाये।

सियासी गहमागहमी

मोदी सरकार की घोर निंदा का परिचायक बनी सिसोदिया की रिहाई

दिल्ली के पूर्व शिक्षामंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें तथा गवाहों को प्रभावित न करें। करीब 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर आते ही आम आदमी पार्टी जश्न में डूब गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। संजय सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सिर झुकाकर नमन करते हैं कि लंबे इंतजार के बाद हमें आखिरकार न्याय मिला। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के पक्ष में आए इस कोर्ट के फैसले से पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है। जाहिर है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई कही न कही मोदी सरकार की घोर निंदा का परिचायक बन गई है।

पटवारी पर हो सकती है कार्यवाही

पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचे थे। यहां एनएसयूआई के छात्रों ने फर्जी बीएड कॉलेजों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल की हुई थी। जीतू पटवारी इनके समर्थन में पहुंचे और जेयू प्रशासन को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। एनएसयूआई के छात्रों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को 80 से ज्यादा अवैध बीएड कॉलेज की जानकारी दी और कहा कि कई स्थान पर जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ही कैंपस में 4 बीएड कॉलेज चल रहे हैं। जहां भवन नहीं है वहां भी बीएड कॉलेज दस्तावेजों में बताए जा रहे हैं। पटवारी के विश्वविद्यालय जैसे स्थान पर इस तरह का अभद्र व्यवहार ने कांग्रेस के शिष्टाचार नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। पटवारी की करतूत कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान पटवारी पर क्या कार्यवाही करता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ-साथ पूरा देश भावुक है।

जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ। आदिवासी वर्ग हमारी वन संपदा और पर्यावरण के प्रथम प्रहरी के रूप में सदैव जाने जाते है।

आदिवासी वर्ग के उत्थान और उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिये कांग्रेस सदैव संकल्पित रही है।

जय जोहार।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

बीजेपी के सच्चे समर्पित नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय

समता पाठक/जगत प्रवाह

मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय एक कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। इंदौर में 13 मई, 1956 को जन्में विजयवर्गीय ने वर्ष 1975 में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में प्रवेश किया। वे वर्ष 1983 में नगर पालिक निगम इंदौर के पार्षद, 1985 में स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा भा.ज.यु. मोर्चा के प्रदेश मंत्री, भा.ज.पा. इंदौर के संगठन मंत्री तथा विदयार्थी मोर्चे के प्रदेश संयोजक रहे। विजयवर्गीय वर्ष 1992 में भा.ज.यु. मो. के प्रदेश उपाध्यक्ष, भा.ज.यु. मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुजरात के युवा मोर्चा प्रभारी वर्ष 2000 से इंदौर पालिक नगर निगम के महापौर अखिल भारतीय महापौर संघ के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष। उन्होंने वर्ष 2001 में चीन एवं अमेरिका तथा 2002 में जोहान्सवर्ग की यात्रा की। वे वर्ष 2002 में भा.ज.पा. के स्थानीय प्रशासन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मनोनीत किये गये। वे वर्ष 2003 में साउथ एशिया महापौर परिषद के संयोजक, भा.ज.पा. मध्यप्रदेश के प्रवक्ता, नंदानगर नवयुवक रामायण मंडल के संस्थापक, रामायण मंडल संगठनों के अध्यक्ष एवं इंदौर के अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से संबद्ध, लकी वाण्डरर्स स्पोट्र्स केयर के संरक्षक रहे। विजयवर्गीय ने भारतीय जनता पार्टी में महासचिव के दायित्वों के निर्वहन के साथ हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

विजयवर्गीय वर्ष 1990 में नौवीं एवं 1993 में दसवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे सार्वजनिक उपक्रम समिति एवं लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1998 में 11वीं, वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री, लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य, नगरीय प्रशासन विकास (सिंहस्थ कुंभ संबंधित कार्य.), धार्मिक न्यास, धर्मस्व व पुनर्वास तदनंतर ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी रहे। विजयवर्गीय वर्ष 2023 में 16वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इन्होंने 25 दिसम्बर, 2023 को मंत्री पद की शपथ ली।

छोटे बांधों में बाढ़ का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य

जगत प्रवाह. भोपाल। बाढ़, एक प्राकृतिक आपदा है, जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में हर साल व्यापक विनाश का कारण बनती है। इस संदर्भ में, छोटे बांध, जिन्हें जल संरक्षण, सिंचाई और स्थानीय जल आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है, बाढ़ के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, गलत प्रबंधन, रखरखाव की कमी और बढ़ते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण ये बांध कभी-कभी बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। इस लेख में, हम छोटे बांधों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक, और सामाजिक समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत जैसे देश में, जहां कृषि पर निर्भरता अधिक है, छोटे बांध जल प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन बांधों का प्राथमिक उद्देश्य जल संग्रहण और नियंत्रित वितरण होता है, जो सूखे के दौरान जल उपलब्धता सुनिश्चित

करता है और अतिवृष्टि की स्थिति में अतिरिक्त जल को रोककर बाढ़ की संभावना को कम करता है। हालांकि, कई बार जल प्रबंधन में कमी के कारण ये बांध संकट का कारण भी बन सकते हैं।

छोटे बांधों में बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक, मानव निर्मित, और प्रबंधन संबंधी कारण शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। अधिक वर्षा और जलवायु परिवर्तनः जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे बांधों पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। बांधों की नियमित देखभाल और मरम्मत न होने से संरचनात्मक कमजोरियाँ विकसित होती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बांधों के आसपास की जल निकासी प्रणाली का अव्यवस्थित होना, जिससे जल के बहाव में रुकावट आती है और जलभराव होता है। स्थानीय प्रशासन और बांध प्रबंधकों की कमी, जिनके पास सही प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी होती है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक उपायों का संतुलित उपयोग हो। आइए, इन उपायों पर विस्तार से चर्चा करें।

(शेष पेज 7 पर)

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

स्वतंत्रता की चेतना के साथ सशक्तीकरण की भावना भी जरूरी

जगत प्रवाह. भोपाल। स्वतंत्रता के इतिहास से तो हम सभी परिचित हैं, हम जानतें हैं कि किन बलिदानों के फल स्वरूप हमें स्वाधिनता मिली। अब हमें वर्तमान पीढ़ी को यह सीखाने की जरूरत है कि स्वतंत्रता की चेतना के साथ सशक्तीकरण की भावना भी जरूरी है। तभी हम देश के विकास को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। तभी देश में उत्साह का संचार संभव हो सकेगा। हमारी अर्थव्यवस्था सुदढ़ होगी और हम हर मोर्चे पर विकास के शिखर तक पहुंच पाएंगे। हमें वर्तमान पीढ़ी में सशक्तीकरण की भावना का विकास करने के लिए इसे चेतना के स्तर पर समझना और समझाना होगा। सशक्तीकरण के लिए जरूरी है कि अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने वांग्मय को लेकर गौरव का अनुभव करें। अपने समृद्ध इतिहास को तलाशने का प्रयास करें और विस्मृत की गई ऐतिहासिक विभूतियों को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करें।

अगर चेतना के स्तर पर जाकर देखें तो भारतवर्ष कभी परतंत्र रहा ही नहीं। आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर आक्रमण करके इस पर कुछ वर्ष तक शासन अवश्य किया, किंतु भारत की सशक्तीकरण की भावना को नष्ट करने में सफल नहीं हो सके। यही कारण है कि भारत अपने स्वतंत्रता के मूल्यों को तमाम विरोधाभासों के बावजूद संजोने में कामयाब रहा, बल्कि भारत का एक बड़ा भूभाग उस सांस्कृतिक एकता को भी कायम रखने में कामयाब रहा जो भारत की मूल अवधारणा से विकसित हुई थी।

स्वतंत्रता दिवस पर हमें बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि हमारी वैदिक परंपरा से लेकर वर्तमान परंपरा तक स्वतंत्रता का हर जगह सम्मान किया गया। केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे की स्वतंत्रता को भी हमने उतना ही महत्व दिया। यही कारण है कि भारत में सभी समाज और सभी वर्ग फले-फूले। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हर वर्ग के राजा-महाराजा और सामंत हुए। 3000 वर्ष के इतिहास में भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हूण, कुषाण, तैमूर, तातार, मुगल, अंग्रेज जैसे आक्रांता इस देश पर समय-समय पर आक्रमण अवश्य

करते रहे लेकिन भारत अपनी आंतरिक स्वतंत्र चेतना के कारण इनसे अप्रभावित रहा, बल्कि भारत भूमि के जिन निवासियों ने आक्रांताओं की धार्मिक परंपराओं को अपनाया उन्होंने भी भारत की संस्कृति को नहीं त्यागा। अतिथि उनके लिए भी देवता ही रहा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को उन्होंने भी अपनाया। और यही उनकी सशक्तीकरण की भावना थी।

आज स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर हमें एक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का बोध होना बहुत आवश्यक है। हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी परिलक्षित होती है कानून का पालन करने से, ईमानदारी बरतने से और मेहनत और लगन से काम करने से। विशेष बात यह है कि यह सारे गुण हमारे भारतीय वांग्मय में और हमारे धर्मग्रंथों में भी लिखे हुए हैं, इसलिए जब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते के सिद्धांत का पालन करते हैं तब राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध स्वतः ही हो जाता है। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाते हैं तो राष्ट्र के हर निवासी के प्रति सद्भाव और सौहार्द स्वतः ही विकसित हो जाता है। यह सब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य का हिस्सा है और यही संविधान में एक व्यवस्था के रूप में हमें प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें सशक्तीकरण की भावना को सच्चे अर्थों में आत्मसात करना है।

15 अगस्त 1947 एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत के जन्म का प्रतीक है, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के दिल को गर्व और देशभक्ति से भर देता है। सशक्तीकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है, क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है।

(शेष पेज 7 पर)

नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता से जलकुंभी से ढक रही बड़ी झील सहित अन्य झीलों की सुंदरता

(पेज 1 का शेष)

इस दौरान तालाबों से जलकुंभी और गाद निकाली जाएगी। कुएं-बावड़ी साफ होंगे। जरूरत हुई तो घाटों की मरम्मत भी होगी।

जलस्रोतों में फेंका जा रहा सिंगल यूज प्लास्टिक

जलकुंभी के अलावा जलस्रोतों में बड़े पैमाने पर सिंगल यूज प्लास्टिक भी फेंका जा रहा है। बड़े तालाब, कलियासोत, मुंशी हुसैन खां और सिद्धीक हसन सहित अन्य तालाबों में प्रतिदिन भारी मात्रा में पन्नी और डिस्पोजल ग्लास डाले जा रहे हैं। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद हुए 5 माह हो गए हैं। लेकिन नगर निगम अधिकारियों के उदासीन रवैए के कारण इस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है।

उदासीन बना बैठा है निगम का झील संरक्षण प्रकोष्ठ

जल स्त्रोतों को सहेजने की कवायद कई स्तरों पर किए जाने की बात कही जाती है, इसके लिए सरकारी महकमे बाकायदा एक्शन प्लान तैयार करते हैं और इसे लागू करने के लिए भारीभरकम राशि भी खर्च होती है, पर मॉनीटरिंग के अभाव में ये योजनाएं अपने उद्देश्यों में सफल होने में नाकाम साबित हो रही हैं। बड़ा तालाब को सहेजने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, वहीं छोटा तालाब और शाहपुरा झील के प्रति बरती जा रही अनदेखी इन जलस्त्रोतों की सेहत बिगाड़ रही है। हालात ये हैं कि जलकुंभी और गाद की पहुंच दोनों ही तालाबों में लगातार बढ़ रही है, वहीं नगर निगम इनकी सफाई को लेकर संजीदा नहीं है।

तालाब किनारे लगे रहने वाले गंदगी के ढेर पहले से ही परेशानी बने हुए थे, वहीं तालाब को लील रही जलकुंभी और गाद को हटाने के लिए नगर निगम ने पहल तक नहीं की है। छोटे तालाब के जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित हिस्से में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित की जाती हैं, यहां तालाब और इसके किनारे फैली गंदगी खिलाडियों के लिए परेशानी का सबब बनी रहती है। ये स्थिति तब है जब पास ही में राजभवन और कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री निवास है। इसके अलावा तमाम विभागों के आला अधिकारियों की आवाजाही यहां से बनी रहती है। कमोबेश यही स्थिति शाहपुरा झील की है। यहां भी गाद और जलकुंभी तालाब को नुकसान पहुंचा रही है।

जलीय जीवन पर भी संकट

छोटा तालाब और शाहपुरा झील में जमी गाद और जलकुंभी के कारण तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। गंदे पानी के कारण मछलियां मर रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा तालाब की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छोटा तालाब स्थित घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचने वालों को तालाब में पसरी गंदगी के कारण परेशानी हो रही है।

जलकुंभी हटाने वाली मशीन खराब

नगर निगम द्वारा छोटे तालाब से जलकुंभी हटाने का कार्य मशीन से किया जा रहा था, पर कुछ महीने पहले भार अधिक होने से ये मशीन तालाब में डूब गई थी। खास बात है कि इस मशीन की मरम्मत में आने वाले भारीभरकम खर्च को देखते हुए इसे जस का तस छोड़ दिया गया है। इसके बाद से तालाबों की सफाई का काम तकरीबन ठप है।

अधिकारी कर रहे स्वच्छता के दावे

छोटा तालाब एवं शाहपुरा झील में जलकुंभी और गाद की वजह से हो रही परेशानी के संबंध में जब नगर निगम अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने तालाब की निरंतर सफाई का दावा किया। हालांकि तालाब में पसरी गंदगी की हकीकत मौके पर देखी जा सकती है।

तालाब में मिल रहे नाले

आसपास की रहवासी बस्तियों से गंदा पानी छोटा तालाब और शाहपुरा झील में मिल रहा है। बाणगंगा क्षेत्र से निकलने वाला नाले का गंदा पानी सीधे ही छोटे तालाब में मिल रहा है, इसी तरह शाहपुरा झील में भी पांच से अधिक नालों से रोजाना हजारों लीटर गंदा पानी मिल रहा है।

करोड़ों रुपये की मशीनें भी हुई खराब

नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ ने करोड़ों रुपए वार्षिक दर पर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है। कंपनी पिछले कई वर्ष से काम कर रही है। इसके बावजूद अब तक झील की सफाई नहीं हो पाई। खास बात यह है कि सफाई के लिए करोड़ों रुपए की जो मशीनें लगी हैं, वह कंपनी की नहीं, बल्कि निगम की ही हैं। मशीनों का मेंटेनेंस कंपनी को करना है। बताया जाता है कि पांच महीने पहले निगम की आधुनिक मशीन सफाई के दौरान झील में समा गई थी। इसे चला रहे ऑपरेटर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। तब से झील की सफाई का काम ठप पड़ा है। छोटे तालाब किनारे मिट्टी और गाद के ढेर लगे हैं। अगर इसे नहीं हटाया गया तो बारिश में यह फिर तालाब में समा जाएगी। यानी नगर निगम के सफाई अभियान पर पानी फिर जाएगा। झील में बड़े पैमाने पर जलकुंभी और खरपतवार उग आई हैं।

नक्सल प्रभावित जिलों में कारगर साबित हो रही है नियद नेल्लानार योजना

(पेज 1 का शेष)

स्थानीय आदिवासी युवाओं से मिलकर बना इस मिलिशिया को तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से समर्थन और प्रशिक्षण दोनों प्राप्त था। परंतु कुछ समय पश्चात इस सलवा जुड़ूम अभियान पर प्रश्न उठने लगे और सन 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने मिलिशिया यानि कि सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे भंग करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुड़ूम पर रोक लगाते हुए यह कहां कि कोई भी अभियान किसी कानून और व्यवस्था को ताक पर रखकर नही चलाया जा सकता। किसी भी नागरिक को आप हथियार देकर किसी की हत्या करने की अनुमति नही दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यकीनन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश ने देश में प्रजातंत्र को और मजबूत किया है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हथियार सिर्फ बदला लेते है बदलाव नही लाते। हालांकि सलवा जुड़ूम की विचारधारा और सोच नक्सलवाद को रोक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की थी। इस अभियान को शुरूआती दौर में बड़ी सफलता भी मिली। यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य से सटे झारखंड और उड़ीसा राज्य भी अपने नक्सली क्षेत्रों में सलवा जुड़ूम जैसे अभियान को शुरू करने की कवायद में थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत 14 नये शिविरों की पांच किमी की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही इन गांव के ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा।

अब हम यहां कह सकते हैं कि नियद नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ को नक्सल मुकत प्रदेश बनने की ओर पहला कदम है। यकीनन यह योजना नक्सली क्षेत्रों की तस्वीर बदलकर आदिवासियों को ना सिर्फ मुख्य धारा में लाने का काम करेगी बल्कि उनके विकास की नई इबारत भी लिखेगी।

साय सरकार की पहल पर बस्तर के 50 गांवों में अब नक्सली बैनर-पोस्टर भी नहीं दिखते हैं, नए पंचायत भवन हुए तैयार

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली गतिविधियों के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले बोदली गांव में नक्सली हलचल खत्म हो गई है। अब यहां नक्सली पोस्टर-बैनर भी नहीं दिखते। कई महीने से गांव में नक्सली गतिविधि नहीं दिखी। इसके लिए न कोई मुठभेड़ हुई और न किसी का सरेंडर कराया गया है। दरअसल, करीब 5 माह पहले गांव में नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) अभियान शुरू हुआ। इसके तहत सबसे पहले गांव की बंद पड़ी राशन दुकान खुलवा दी गई। इसमें अनाज और दूसरी जरूरी चीजों का भंडारण किया गया। फिर नया पंचायत भवन बना। अस्पताल और प्राइमरी स्कूल खोले गए। नल-जल के तहत घर-घर पानी पहुंचा रहे। अधूरी पड़ी पुलिया का निर्माण कराया गया। इससे गांव शहर से जुड़ गया। गांव के शहर से जुड़ने और गांव में मूलभूत सुविधाओं के पहुंचने से नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी।

आपका अच्छा गांव मुहिम ने बदली तस्वीर

गांव के सोमारू बताते हैं कि पहले पुलिस कैंप से ही सारी सुविधाएं मिलती थीं। नक्सली आते थे तो गांव के पिछड़ेपन की कहानी बताकर युवाओं, महिलाओं और बच्चों को बरगलाते थे। अब गांव में मूलभूत सुविधाओं के आने से नक्सलियों का गांव में आना-जाना भी लगभग बंद हो गया है।

नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुई

जिन गांवों में अभियान चल रहा है, वहां नक्सली जड़ें कमजोर हो गई हैं, लोगों का सरकार के प्रति नजरिया बदल गया है बोदली अकेला गांव नहीं है, जहां विकास होने से नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं। बस्तर संभाग के 50 गांवों में विकास के जरिए नक्सली गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं

इन 50 गांवों में नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत चुने गए गांवों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मुफ्त बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गांवों को सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले के उन गांवों को योजना के अंतर्गत लाया गया है, जो गांव पुलिस कैंप से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। यहां पुलिस कैंप खोलने के बाद भी लोग प्रशासन और सरकार से नहीं जुड़ रहे थे। हालांकि सारी सुविधाएं इन कैंपों के जरिए ही लोगों को मिल रही थीं। इसलिए लोगों को विकास के रास्ते जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ में 375 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पांच महीने से बस्तर में सुरक्षा बलों का हौसला लगातार बुलंद है और एक के बाद एक सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच हो रही मुठभेड़ में नक्सली मुंह की खा रहे हैं। पांच महीने के भीतर 120 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार ने जिस तरह मोर्चा खोला है ,उससे नक्सली बैकफुट पर हैं। यही कारण है कि वह हथियार छोड़ रहे हैं। बस्तर में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 375 ने आत्मसमर्पण किया। तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोडमैप पर साय सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह का रोडमैप है कि नक्सलियों के आर्थिक स्त्रोतों की पूरी तरह नाकेबंदी कर उन्हें मिलने वाले फंड को रोका जाए। इसका असर भी शुरू हो गया है। साथ ही नक्सलियों को मिलने वाले हथियारों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पहली बार नक्सलियों से भी सरकार ने मांगा सुझाव

नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खून-खराबा नहीं चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री ने ईमेल और गूगल फार्म जारी करके आम जन और नक्सलियों से भी उनके आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास नीति के लिए सुझाव मांगा है।

क्या रीजनल इन्वेस्टर समिट और राउंड टेबल से आ रहे निवेश के प्रस्ताव बदल पायेंगे प्रदेश की तस्वीर?

(पेज 1 का शेष)

1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भागीदारी

जबलपुर में 1500 से अधिक निवेशकों की भागीदारी रही। आयोजन में बायर-सेलर मीट भी रखी गई, जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इसमें ब्रिटेन, कोस्टारीका, फिजी, ताइवान और मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल भी भाग लिया और कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। कॉनक्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए। रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव के बाद 7 और 8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारियां शुरू हो जायेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की नई निर्यात नीति की घोषणा होगी और निवेश बढ़ाने के लिए नये निवेशकों के साथ नई उद्योग नीति में किए गए प्रावधानों को सांझा किया जाएगा।

360 एकड़ में विकसित हो रहा है

मध्यप्रदेश का निवेश परिदृश्य सकारात्मक रूप से बदल रहा है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यह 222.77 करोड़ रूपये की लागत से 360 एकड़ में विकसित हो रहा है। इसी प्रकार धार में पीएम मित्रा-पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल एंड एपेरेल पार्क भी आकार ले रहा है। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए है और यह 1563 एकड़ में फैला है। नर्मदापुरम में 227 एकड़ में मैन्यूफैक्चरिंग जोन फार पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट भी अपना स्वरूप ले रहा है। इस पर 464.65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा मुरैना में मेगा लेदर फुटवियर एसेससरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क 161 एकड़ में बन रहा है जिसकी लागत 222.81 करोड़ रुपए आएगी। इस प्रकार इन चारों परियोजनाओं पर 1910.23 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया

राज्य सरकार प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सुनियोजित प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश में निर्माण क्षेत्र में सुधार आने के साथ ही प्रदेश से विदेशी निर्यात की अपार संभावनाएं बनी है। अब विदेश व्यापार नीति के अनुसार मध्यप्रदेश ने निर्यात पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यम, किसान और किसान उत्पादक संगठनों, कलाकारों के हस्तशिल्प प्रोडक्ट और उद्यमियों के स्टार्टअप को सहयोग दिया जा रहा है। (शेष अगले पेज पर)

कलम के सिपाही...

शब्दों का प्रयोग कर गजल का स्वरूप देने में माहिर थे गजलकार दुष्यंत कुमार

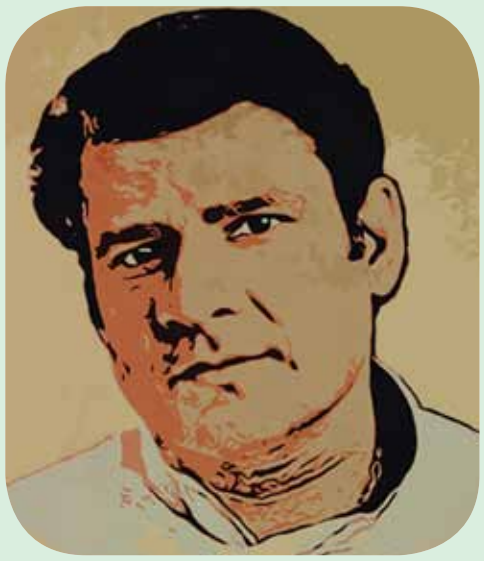

अत्यंत लोकप्रिय हिंदी ग़ज़लकार दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में 1 सितम्बर, 1933 को हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था और उन्होंने अपने काव्य-लेखन का आरंभ दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से किया था। कविताएँ दसवीं कक्षा से ही लिखने लगे थे जिसे आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिनों नया आयाम मिला। इन दिनों वह 'परिमल' और 'नए पत्ते' जैसी संस्थाओं के साथ सक्रिय रहे और उन्हें इलाहाबाद में सक्रिय साहित्यकारों का सान्निध्य मिला। उन दिनों इलाहाबाद में कमलेश्वर, मार्कण्डेय और दुष्यंत की मित्रता लोकप्रिय रही थी। वह कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास सदृश विधाओं में एकसमान लेखन करते रहे थे लेकिन उन्हें कालजयी लोकप्रियता ग़ज़लों से प्राप्त हुई। 'हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं' जैसी पंक्तियों के साथ समय की विडंबनाओं को प्रश्नगत करती उनकी अभिव्यक्ति संसद से सड़क तक गूँजती है और आम आदमी उनमें अपनी आवाज़ की तलाश कर पाता है। लोगों की जुबाँ पर चढ़ी उनकी ग़ज़लें समय की परख करने और उससे लड़ने का हथियार बन सामने आती हैं।

'सूर्य का स्वागत', 'आवाज़ों के घेरे', 'जलते हुए वन का वसंत' उनके काव्य-संग्रह हैं जबकि 'छोटे-छोटे सवाल', 'आँगन में एक वृक्ष' और 'दुहरी ज़िंदगी' के रूप में उन्होंने उपन्यास विधा में योगदान किया है। 'और मसीहा मर गया' उनका प्रसिद्ध नाटक है और 'मन के कोण' उनके द्वारा रचित एकांकी है। उन्होंने 'एक कंठ विषपायी' शीर्षक काव्य-नाटक की भी रचना की है। उनके स्थायी यश का आधार उनका इकलौता ग़ज़ल-संग्रह 'साये में धूप' है जिसकी दर्जनाधिक ग़ज़लें हिंदी-देश के संवाद और संबोधन में रोज़मर्रा का साथ निभाती हैं।

30 दिसम्बर 1975 को महज 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। 'दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय' में उनकी धरोहरों को सँभालने का प्रयास किया गया है।

क्या रीजनल इन्वेस्टर समिट...

(पिछले पेज का शेष)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश से निर्यात की संभावनाओं का आंकलन कर ऐसे उत्पादों की निर्यात सूची बनाई गई है, जिनकी विदेशी बाजार में मांग है।

जिलों में निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर सभी जिलों में निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ बन गए हैं। इससे छोटे और मझौले स्तर के उत्पादकों में निर्यात के प्रति जागरूकता आई है। मध्यप्रदेश व्यापार संगठन परिषद और निर्यात प्रकोष्ठों ने मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किये हैं जिससे निवेश की संभावनाओं का आंकलन करने में सरकार को मदद मिली। नीमच, हरदा, अशोकनगर, नरसिंहपुर, शहडोल, बालाघाट, बैतूल और धार में जिला निर्यात संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रदेश भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में योगदान बढाने की दिशा में प्रयासरत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दवा उत्पाद, कपास, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीन, कपड़ा, जैविक रसायन, एल्युमिनियम, धातु, अनाज, विद्युत मशीनरी उपकरण, प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट का निर्यात हुआ है। सबसे ज्यादा दवा उत्पादों का निर्यात हुआ। इनका निर्यात मूल्य 13,158 करोड़ रूपये है।

दोगुना निर्यात का लक्ष्य

अगले तीन सालों में मध्यप्रदेश का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला जिला है, जिसने 20,256 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इसके बाद धार, रायसेन और सीहोर जिलों से ज्यादा निर्यात हुआ। धार से 10,973 करोड़, रायसेन से 7561 करोड़ रुपए, सीहोर से 4,045 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ। मोहन सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। बड़े निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक निवेश की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिये राज्य में एक कस्टमाइज पैकेज का प्रावधान भी है। निवेश प्रक्रिया और अनुमोदन को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली काम कर रही है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 12 विभाग सूचीबद्ध है और 46 सेवाएं उपलब्ध है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2024-25 के बजट में आकर्षक प्रावधान किए हैं। निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 2000 रुपए का बजट प्रावधान किया है। औद्योगीकरण विकास के लिए 490 करोड़ रुपए, भू-अर्जन, सर्वे और सर्विस चार्ज के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए निवेश संवर्धन सुविधा प्रदान करने के लिए 699 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भविष्य में उदयोगों के संवर्धन में गति आयेगी।

निवेश की अच्छी शुरूआत

रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की शुरूआत उज्जैन से हुई थी। इसमें एग्रो ऑयल एंड गैस कंपनी ने 75 हजार करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। जेके सीमेंट ने 4000 करोड़, वोल्वो ने 1500 करोड़, एशियन पेंट्स ने 2000 करोड़, एचईजी ने 1800 करोड़, हिंदुस्तान इंजीनियर इंडस्ट्रीज ने 1500 करोड़, एलएनटी माइंड ट्री ने 800 करोड़, पेंशन ग्रुप में 400 करोड़ और ओरिएंटल पेपर मिलने 980 करोड़ रूपये निवेश करने की सहमति दी। इन एक लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के पूरा होने से लगभग 01 लाख से ज्यादा रोजगार का निर्माण होगा। इसी प्रकार मुंबई इंडस्ट्री कान्क्लेव में प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और एक लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा।

400 करोड़ रुपए निवेश का वादा

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 450 करोड़ रुपए, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने 50 हजार करोड़ रुपए, ग्रासिम इंडस्ट्री ने 4000 करोड़ रुपए, जेएसडब्ल्यू लिमिटेड ने 17000 करोड़ रुपए, जोत डाटा सर्विस ने 500 करोड़ और एलएनटी ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया। पर्यटन के क्षेत्र में महिंद्रा हॉलिडे ने 750 करोड़ रुपए और ओबेरॉय होटल समूह ने 400 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है।

मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद

रीजनल स्तर पर ऐसे प्रयासों से क्षेत्र एवं आसपास के निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करने पर फोकस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह अनूठा प्रयास है। इन प्रयासों से मध्यदेश में औदयोगिक निवेश की गति तेज हो गई है। कनेक्टिविटी, उदयोग-मित्र नीतियों और उदयोग-अनुकूल अधोसंरचनाओं से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है

छोटे बांधों में बाढ़ का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य

(पेज 5 का शेष)

जल स्तर की निगरानी के लिए उन्नत सेंसर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे बांधों में जल स्तर के अचानक बढ़ने की स्थिति में समय रहते चेतावनी प्राप्त हो सकती है। आधुनिक तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग जलवायु पूर्वानुमान में सुधार कर सकता है।

बांधों की संरचनात्मक मजबूती के लिए नियमित निरीक्षण और मरम्मत कार्यों को अंजाम दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग के नवीनतम मानकों का उपयोग करके बांधों की संरचना को सुदृढ़ किया जा सकता है। बांधों के आसपास की जल निकासी प्रणाली को सुधारना जरूरी है ताकि जल का प्रवाह सुगम हो सके और जलभराव की समस्या ना हो। इस हेतु, प्राकृतिक जल निकासी को बहाल करना और कृत्रिम जल निकासी संरचनाओं का निर्माण करना आवश्यक है।

हर छोटे बांध के लिए एक आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें संभावित बाढ़ के परिदृश्यों के लिए तैयारियों का विस्तार हो। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का गठन, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, और लोगों की सुरक्षा के लिए योजनाएं शामिल होनी चाहिए। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है। यह समन्वय बाढ़ की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

जल संसाधन प्रबंधन के लिए स्थापित नियमों और नीतियों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जल निकासी पर असर ना पड़े। स्थानीय समुदाय को बाढ़ प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समुदाय के सदस्यों को जल प्रबंधन और आपदा तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ले सकें। स्थानीय स्तर पर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे लोग बाढ़ की आपदा के प्रति जागरूक हों और सही समय पर सही कदम उठा सकें। छोटे बांधों के प्रबंधन को स्थानीय विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि सामुदायिक विकास के साथ-साथ जल प्रबंधन में भी सुधार हो सके।

भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां छोटे बांधों के कुशल प्रबंधन से बाढ़ की समस्याओं का सफल समाधान किया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में समुदाय आधारित जल प्रबंधन कार्यक्रम ने छोटे बांधों की भूमिका को प्रभावी रूप से बढ़ाया है। इस पहल के अंतर्गत स्थानीय लोगों को जल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया और बांधों की निगरानी और रखरखाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। छोटे बांधों में बाढ़ का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, जल प्रबंधन के नए तकनीकी समाधान और स्थानीय समुदायों की सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए शोध और अध्ययन किए जाने चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। नवीन तकनीकों जैसे GIS (Geographic Information System) और रिमोट सेंसिंग का उपयोग जल प्रबंधन में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। छोटे बांधों के प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे संसाधनों की उपलब्धता और प्रबंधन में सुधार हो सके। (जगत फीचर्स)

स्वतंत्रता की चेतना के साथ सशक्तीकरण की भावना भी जरूरी

(पेज 5 का शेष)

अंतर-राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है। फिर भी, सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली GDP growth भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञान-विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है बल्कि हमारे लिए वे मानवता के विकास के साधन हैं। एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वह है - जलवायु परिवर्तन। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है। इन सब का एक प्रमुख कारण Global Warming को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित हैं। आइए, हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाई-चारे की भावना के साथ आगे बढ़ें।

आज इसी सशक्तीकरण की भावना को जीवित करने और अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता है। तभी स्वतंत्रता सार्थक और मूल्यवान बन सकेगी। हम सब अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकें। भारतवर्ष को विश्व में अग्रणी बना सकें। ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना में विश्व में सर्वोपरि बन सकें... इस स्वतंत्रता दिवस पर यही कामना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं।

(जगत फीचर्स)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़

खुशियों का गढ़

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हम खुश हैं
क्योंकि हम किसानों से किए गए वादे पूरे हुए हैं। हमें दो साल का बकाया बोनस मिला है।

हम खुश हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब हम क्षेत्रीय बोली-भाषा में भी पढ़ पाएंगे। हमारी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमारे विष्णु देव सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम खुश हैं
क्योंकि हम सरकार को ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान बेचते हैं, जो भारत में सबसे अधिक कीमत है। इस साल राज्य में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।

हम खुश हैं
क्योंकि हमें कई सालों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का पक्का घर मिला है।

हम खुश हैं क्योंकि हमारी तरह राज्य की 70 लाख बहनों को महतारी वंदन योजना से प्रति माह ₹1000 मिलते हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

हम खुश हैं क्योंकि हमें हमारे परिश्रम का सम्मान मिला- तेंदूपत्ता संग्रहण की दर ₹4000 से ₹5500 बढ़ा दी गई और खरीदी की समय-सीमा भी बढ़ाई गई। हरा सोना अब बना खरा सोना।

हम खुश हैं
क्योंकि हम युवाओं को सरकारी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु में 5 वर्ष की छूट मिली है। अब रोज़गार के नए रास्ते खुल गए।

हम खुश हैं
क्योंकि जनदर्शन में हज़ारों लोग प्रदेश के मुखिया से मिल पा रहे हैं, अपनी समस्याएं सुनाकर त्वरित निवारण पा रहे हैं।

हम खुश हैं क्योंकि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। विष्णु देव सरकार की जीरो टॉलेरेंस नीति राज्य में सुशासन ला रही है।

हम खुश हैं
क्योंकि हमारे श्रवण कुमार विष्णु देव हमें निःशुल्क अयोध्या-काशी तीर्थ भ्रमण करा रहे हैं। इस जीवन में हमने रामलला दर्शन योजना से जीवन का पुण्य पा लिया।

हमसे जुड़ने के लिए
QR CODE स्कैन करें।

RO No. 12862/1

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)